IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सरकार की विभिन्न योजनाओं से कृषि में नवाचार एवं ग्रामीण विकास

(दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)

[1]ज्योति निषाद [2]डॉ.(श्रीमती) संतोष जैन

[1]शोधार्थी (अर्थशास्त्र) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

[2]शोध निर्देशक (वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक–अर्थशास्त्र) कल्याण स्ना. महा. सेक्टर–7 भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

Abstract : भारत विविधताओं का देश है, जहाँ भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विविधताएँ दृष्टव्य होते हैं। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है तथा अधिकतम परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति कृषि के माध्यम से होती है। श्री धर्मेन्द्र कन्नौजे का कथन है ''भारत के विकास में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता की आवश्यकता है, कृषि असफल तो देश असफल''। आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में सभी वर्गों का अस्तित्व है किन्तु उच्च वर्ग की तुलना मे निम्न वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है जो गाँव मे निवास करती है। वैसे तो भारत देश 1947 से आजाद हो गया है, किन्तु सही मायने में आजादी का महत्व तब साकार होगा जब भारत में सभी लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत् सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों का विकास करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। ग्रामीण जनसंख्या जो कि कृषि पर आश्रित है, साथ ही साथ देश की शहरी एवं नगरीय जनसंख्या अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि पर ही निर्भर है। अतः सार्थक रूप से देश के आर्थिक विकास हेतु कृषि के माध्यम से ग्रामीण विकास की भूमिका सबसे अधिक है। प्रस्तुत शोध पत्र मे कृषि में नवाचार एवं ग्रामीण विकास के संबंध में प्रकाष डाला गया है।

शब्दकुंजी : कृषि नवाचार, ग्रामीण विकास, कृषि विकास की योजनाएँ, कृषि एवं अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आधारभूत स्तम्भ के रूप मे रही है तथा सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कृषि ग्रामीणों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। भारत मे ज्यादातर कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए मानसून पर आधारित है, इसलिए सरकार बाँध व नहरों द्वारा तथा सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सुधारने का प्रयास कर रही है, साथ ही ग्रामीण विकास हेतु लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना सरकार के प्रोत्साहन से सम्पूर्ण भारत मे की गई है। देश के आर्थिक विकास में द्वितीयक क्षेत्र अर्थात् उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि उत्पाद से ही होती है।

देश आजादी से पूर्व भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि अनेक समस्याओं से जुझता रहा है। आजादी के उपरान्त भारत देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य मे पंचवर्षीय योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक, विभिन्न कृषि एवं ग्रामीण योजनाओं (यथा– मनरेगा, आवास योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान सम्मान निधि योजना एवं सोलर पंप योजना इत्यादि) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में व्याप्त समस्याएँ दूर ही नही हुई, बल्कि आज किसानो एवं ग्रामीणो की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा शासन का केन्द्रीयकरण का एक रूप पंचायती राज प्रशासन और जनता को जोड़ने में तथा ग्रामीणों के समस्याओं के उन्मूलन सहित कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

कृषि का देश के आर्थिक विकास में प्रारम्भ से योगदान रहा है। कृषि में हरित क्रांति, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग एवं आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से उच्च उत्पादकता की प्राप्ति तो हुई है, साथ ही देश में खाद्यान संकट भी दूर हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत् गोबर एवं गो–मूत्र खरीदी कर उसे उर्वरक एवं जैविक खाद के रूप मे उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे रसायनिक खाद का उपयोग कम हो सके और स्वास्थ्यवर्धक एवं उच्च गुणवत्ता वाले खाद्यानों का उत्पादन किया जा सके। इस तरह कृषि देश के आर्थिक विकास की परिकल्पना को पूर्ण करते हुए अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण विकास की नींव कृषि है।

पूर्व साहित्य का अध्ययन

झा, सिद्धार्थ (2016) ने ''गाँवो की बुनियादी विकास में पंचायतो की भूमिका'' में लिखा है कि जब कभी आप गाँवो की चमकती सड़कों, 24 घण्टो बिजली व पानी की सुविधा, गाँवो के पक्के मकान ये सब देखकर चौंक जाये तो समझ लीजिये, कि गाँव का विकास हो रहा है।

त्रिपाठी, स्मिता (1999) ने ''योजना काल में भारतीय कृषि तकनीकी परिवर्तन एवं विकास'' में यह बताया है कि योजना काल में भारत में कृषि की पुरानी तकनीक के स्थान पर नयी तकनीक को अपनाया गया है जिससे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई है।

गुप्ता, रविन्द्र कुमार (2009) ने ''कृषि की अभिनव तकनीक तथा समंवित ग्रामीण विकास एवं नियोजन'' में कृषि के अभिनव तकनीक के माध्यम से किसानो एवं कृषि क्षेत्रो में हुए लाभ को बताया है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अन्तर्गत् विभिन्न सरकारी योजना तथा आर्थिक आयामों की चर्चा की है।

उद्देश्य

1. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा कृषकों एवं ग्रामीणों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. कृषि से प्राप्त आय का ग्रामीणों के विकास पर पड़नें वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना

1. कृषकों की आय में वृद्धि से ग्रामीणों के विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
2. सरकार द्वारा कृषकों एवं ग्रामीणों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ कृषकों एवं ग्रामीणो को मिल रहा है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोध प्रविधि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो उपभागों में बांटा गया है–

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय

भारत के मध्यप्रदेश राज्य से अलग हुआ छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि कृषि एवं उद्योग का गढ़ माना जाता है, जिसमें दुर्ग जिले के तहसील धमधा जो कि विकासखण्ड एवं जनपद पंचायत है। धमधा दर्ग जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग–बेमेतरा मार्ग (SH-7) पर स्थिति है तथा धमधा विकासखण्ड के अन्तर्गत् 116 ग्राम पंचायत व 162 ग्राम है। धमधा विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 2,04,491 है एवं विकासखण्ड में किसानों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए यह क्षेत्र बहुतायत रूप से कृषि का गढ़ है जिसमे कृषि के माध्यम से ग्रामीणों का विकास परिलक्षित है। इस क्षेत्र को प्रस्तुत शोध पत्र के शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है।

2. आकड़ो का संकलन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ो के संकलन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के धमधा विकासखण्ड का चयन किया गया है जिसमें दैव निदर्शन पद्धति के अन्तर्गत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 250 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं से प्रश्नावली, अनुसूची एवं अवलोकन विधि द्वारा आंकड़ो को एकत्रित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में आवश्यकतानुसार द्वितीय आंकड़ो के संकलन के लिए संबंधित ग्रंथो का अध्ययन किया गया है।

तालिका क्रमाँक–1

विभिन्न कृषि एवं ग्रामीण संबंधित सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति

क्र.	योजनाओं का नाम	लाभ हुआ	लाभ नही	योग
1	किसान सम्मान निधि	201	49	250
2	राजीव गांधी किसान न्याय योजना	250	0	250
3	सोलर पंप सिंचाई योजना	35	215	250
4	नहर सिंचाई योजना	170	80	250
5	किसान क्रेडिट कार्ड योजना	235	15	250
6	मनरेगा के तहत् भूमि सुधार	190	60	250
7	उन्नत बीज एवं खाद्य वितरण योजना	250	0	250
8	गोधन न्याय योजना	135	115	250
9	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	225	25	250
10	प्रधानमंत्री आवास योजना	80	170	250
11	स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण	250	0	250
12	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	175	75	250
13	नल जल योजना	95	155	250
14	किसानो की ऋणमाफी	110	140	250

स्रोत : प्रश्नावली/अनुसूची द्वारा संकलित।

आरेख क्रमाँक–1
विभिन्न कृषि एवं ग्रामीण संबंधित सरकारी योजनाओं के लाभ की स्थिति

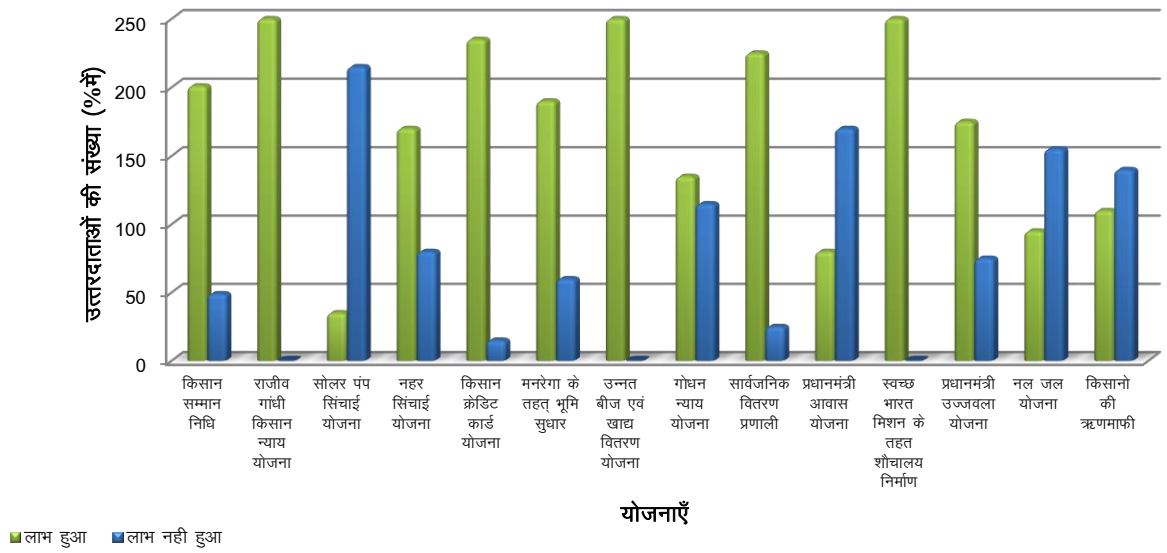

तालिका व आरेख क्रमाँक–1 से स्पष्ट होता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उन्नत बीज एवं खाद्य वितरण, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण योजना का लाभ 100 प्रतिशत लोगों को मिला है तथा सबसे कम 35 उत्तरदाताओं को सोलर पंप सिंचाई योजना का लाभ मिला है, साथ ही किसान सम्मान निधि 201, नहर सिंचाई योजना 170, किसान क्रेडिट योजना 235 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 225 उत्तरदाता परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है।

तालिका क्रमाँक–2

किसानों एवं ग्रामीणों के आय में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में परिवर्तन की स्थिति

क्र.	परिवारिक स्थिति में विभिन्न परिवर्तन	हुआ है	नही हुआ है	योग
1	मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति	210	40	250
2	राशन की व्यवस्था	250	0	250
3	शिक्षा का स्तर	170	80	250
4	पक्का घर निर्माण	145	105	250
5	पेय जल की व्यवस्था	155	95	250
6	24 घण्टे बिजली की व्यवस्था	105	145	250
7	डिजिटल सुविधायें	140	110	250
8	पलायन में कमी	230	20	250
9	रोजगार में वृद्धि	175	75	250
10	आधुनिक कृषि यंत्र	80	170	250

स्रोत : प्रश्नावली/अनुसूची द्वारा संकलित।

आरेख क्रमाँक–2
किसानों एवं ग्रामीणो के आय में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में परिवर्तन की स्थिति

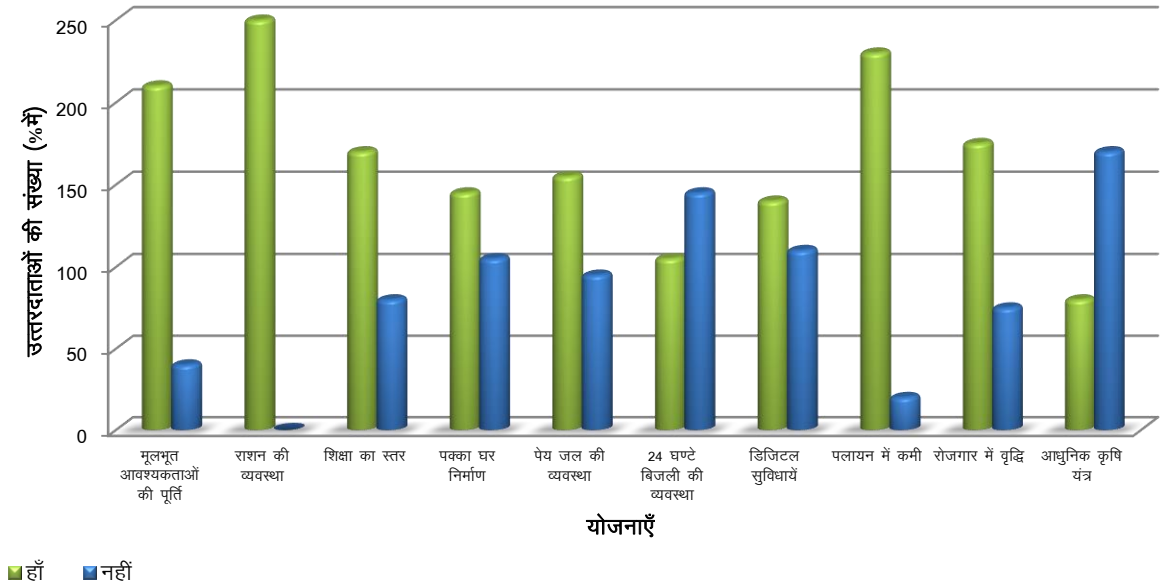

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओ में राशन की व्यवस्था 100 प्रतिशत है तथा आधुनिक कृषि यंत्र की उपस्थिति 80 उत्तरदाताओं के पास उपलब्ध है। इसी के साथ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति 210, शिक्षा के स्तर में वृद्धि 170, पलायन में कमी 230 एवं 175 उत्तरदाताओं के परिवार में रोजगार में वृद्धि हुई है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ कृषकों एवं ग्रामीणो को मिल रहा है, साथ ही किसानो एवं ग्रामीणो के आय में, रोजगार में, शिक्षा के स्तर में, मूलभूत सुविधाओं के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन का परिचायक गाँवों में पेय जल की व्यवस्था, पक्के सड़क, गलियों का सीमेंटीकरण, पक्के नालियाँ, बिजली के खम्भो में लैंपो की व्यवस्था, पंचायतों में डिजिटल सुविधायें और पक्के मकान जिसमें 24 घण्टे बिजली की सुविधा इत्यादि हैं। आज गाँवो की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि पूरे देश के सर्वांगीण विकास की नींव एवं राजनैतिक पहलू की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई अपना सम्पूर्ण विकास कर रही है। ग्राम पंचायतो को भारत का लघुदर्पण कहा जाता है। आज कृषि के माध्यम से ग्रामीण अपनी जीवन प्रत्यासा को बढ़ाते हुए रोजगार के उच्च स्तर पर पहुच रहे है और गाँव के अन्तिम छोर पर खड़े मजदूर का जीवन खुशहाल हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था की नींव कृषि आज ग्रामीणो के साथ–साथ पूरे देश का भरण–पोषण खाद्यान के माध्यम से कर रही है साथ ही स्वयं के विकास के साथ देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

संदर्भ

1.गुलाटी, अशोक एवं टिम केली (2003): व्यापार उदारीकरण और भारतीय कृषि, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली.

2.जी.एस. भल्ला (2007): इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, एन.बी.टी. नई दिल्ली.

3.सिंह, करतार (2009): ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन, कृषि, तीसरा संस्करण.

4.विश्व बैंक (2008): विश्व विकास रिपोर्ट : विकास के लिए कृषि, द वर्ड बैंक वाशिंगटन, डी.सी.

5.मीणा, जनक सिंह (2010): ग्रामीण विकास के विविध आयाम.

6.त्रिपाठी, संजय (2010): छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ.

7.त्रिपाठी, राजपूत (2007) कृषक दूत, धान की उन्नत खेती, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.

8.मिश्रा, जे. पी. संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन.

9.राठौर, सुमनलता (2020): आधुनिक कृषि प्रणाली का फसल उत्पादन पर प्रभाव, इंटरनेशनल जनरल ऑफ सोसल साइंस एण्ड मैनेजमेंट स्टडी, पृ.सं. 81–85.

10.सिंह, आर.एन. (2020): प्रजातंत्र की नींव ग्राम पंचायतो का ग्रामीणों के कायाकल्प में अद्वितीय भूमिका, इंटरनेशनल जनरल ऑफ सोसल साइंस एण्ड मैनेजमेंट स्टडी, पृ.सं. 92–95.

11.https://kishan_jagran.com

12.https://wikipedia.com